चाइना ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का दम, आयुष शेट्टी की बड़ी जीत

Page-04

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

स्टारडम बनाम कहानी: क्या केवल विजय का करिश्मा काफी है?

Page-05

देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान

सरकार का खुला न्योता—क्या संवाद से निकलेगा NEET विवाद का समाधान?

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद अब दिल्ली की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। राजधानी में कई दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 24 जुलाई को देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन ने अपने समर्थकों से अपील की है कि आंदोलन को केवल जंतर-मंतर तक सीमित न रखा जाए, बल्कि हर शहर और हर गांव में शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई जाए। इस घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आंदोलनकारी छात्रों और CJP को बातचीत का खुला निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है तथा छात्र प्रतिनिधियों को चार औपचारिक प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम टकराव और संवाद के बीच संतुलन तलाशने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य आंदोलन को दबाना नहीं, बल्कि छात्रों की चिंताओं को समझकर समाधान निकालना है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों की मांगों और अन्य सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। सरकार का मानना है कि बातचीत के माध्यम से ही ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है, जिससे छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। सरकार लगातार यह भी दोहरा रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सुधारों पर काम चल रहा है।

राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले-

युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रही है और इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के करोड़ों युवाओं को उठाना पड़ा है। उनका कहना था कि जिन छात्रों ने वर्षों तक मेहनत कर

मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की, उनके विश्वास को सबसे अधिक चोट पहुंची है। राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने पेपर लीक के मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की घोषणा की है।राहुल गांधी ने कहा कि सरकार केवल नई घोषणाएं करने के बजाय यह बताए कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था कैसे विफल हुई। उनके अनुसार, यदि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती, तो लाखों छात्रों को मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है और इस मामले में सरकार को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि पेपर लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि छात्रों का विश्वास बहाल करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि विपक्ष का मानना है कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी और अदालतें की घोषणा पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल लगातार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने, परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और व्यापक संस्थागत सुधारों की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि यदि जवाबदेही तय नहीं होगी, तो भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वे लाखों छात्र हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत के बाद परीक्षा दी और अब निष्पक्ष व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अधिक आवश्यक यह है कि परीक्षा प्रणाली को इतना मजबूत बनाया जाए कि भविष्य में किसी भी छात्र के मन में उसकी निष्पक्षता को लेकर संदेह न रहे। यही इस पूरे विवाद का सबसे स्थायी और प्रभावी समाधान माना जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट

देशभर में NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर जारी राजनीतिक और सामाजिक बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा।प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता देश के करोड़ों छात्रों के विश्वास से जुड़ी हुई है। यदि परीक्षा प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को उठाना पड़ता है जिन्होंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया होता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके। हालांकि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद भी राजनीतिक बहस थमती नजर नहीं आ रही है। विपक्ष का कहना है कि केवल नई अदालतों की घोषणा पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आखिर परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और भविष्य में इसे रोकने के लिए कौन-कौन से संस्थागत सुधार किए जाएंगे।

जंतर-मंतर पहुंचे अलख पांडे

छात्रों के समर्थन में सरकार से संवाद की अपील

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच फिजिक्सवॉला (Physics Wallah) के सह-संस्थापक और सीईओ अलख पांडे का जंतर-मंतर पहुंचना पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब तक आंदोलन से दूरी बनाए रखने के आरोप झेल रहे अलख पांडे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचकर उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सरकार से अपील की कि वह छात्रों के साथ सीधे संवाद स्थापित करे। उनके इस कदम के बाद शिक्षा जगत और सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है कि देश के प्रमुख शिक्षकों और शिक्षा उद्यमियों की ऐसी परिस्थितियों में क्या भूमिका होनी चाहिए।दरअसल, पिछले कुछ दिनों से आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (C J P) अलख पांडे की आलोचना कर रही थी। संगठन का आरोप था कि देश के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में शामिल होने के बावजूद उन्होंने छात्रों के आंदोलन पर खुलकर अपनी बात नहीं रखी। इतना ही नहीं, संगठन ने उन शिक्षकों के बहिष्कार तक की अपील की थी जो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में अलख पांडे का जंतर-मंतर पहुंचना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रदर्शन स्थल पर छात्रों को संबोधित करते हुए अलख पांडे ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखने के बजाय छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए। उनका कहना था कि संवाद ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रभावी माध्यम है और सरकार तथा छात्रों के बीच सीधी बातचीत से ही इस विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है।

जंतर-मंतर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की FIR

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों पर कथित हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विस्तृत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया, जिसमें दो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस मामले में हत्या की कोशिश, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।दिल्ली पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरुआत में स्थिति सामान्य थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और कथित उपद्रवियों ने पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने कहा कि घायल अधिकारियों का उपचार कराया गया है और घटना से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी संगठनों ने पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और बल प्रयोग पहले पुलिस की ओर से किया गया। उनका कहना है

कि बड़ी संख्या में छात्र केवल परीक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पहुंचे थे। आंदोलनकारी संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।इस घटना के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के बीच अंतर किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश की नजर इस मामले पर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर न केवल चल रहे छात्र आंदोलन पर पड़ेगा, बल्कि कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को लेकर भविष्य की बहस पर भी दिखाई दे सकता है।

दिल्ली पुलिस का दावा

'बाहरी उपद्रवियों ने बिगाड़ा प्रदर्शन का माहौल'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन ने गुरुवार को नया मोड़ ले लिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पथराव के पीछे मूल प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि बाहरी असामाजिक तत्वों की भूमिका रही। पुलिस के अनुसार, आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी भीड़ में शामिल हो गए, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और हालात को हिंसक बना दिया। इस घटना में दो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) समेत छह पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर मौजूद वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि प्रदर्शन के अंतिम चरण में कुछ ऐसे लोग भी भीड़ में शामिल हो गए थे, जिनका छात्र आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने, बैरिकेड तोड़ने और सुरक्षाबलों पर पथराव करने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को आवश्यक कदम उठाने पड़े। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की किसी भी दूसरी ओर, आंदोलन से जुड़े संगठनों ने पुलिस के इन दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और यदि किसी प्रकार की हिंसा हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी नेताओं का आरोप है कि पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए बाहरी तत्वों की कहानी पेश की जा रही है। उनका कहना है कि यदि वास्तव में उपद्रवी शामिल थे, तो उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे आंदोलन को हिंसक बताना उचित नहीं होगा।घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों ने भी इस घटनाक्रम पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्षी नेताओं ने घटना की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को कानून-व्यवस्था का मुद्दा बनाकर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं सत्तापक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान किया जाएगा, लेकिन हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा।

पुलिसकर्मी की कथित धमकी का वीडियो वायरल, मुंबई पुलिस ने जांच के दिए आदेश

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में जारी छात्र आंदोलनों के बीच मुंबई से सामने आए एक वायरल वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में एक पुलिस वाहन का चालक कथित तौर पर हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों को धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय रिकॉर्ड किया गया, जब छात्र प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस हिरासत में लेकर वैन के जरिए ले जाया जा रहा था। वायरल वीडियो में कथित तौर पर पुलिसकर्मी छात्रों को चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि वे दोबारा प्रदर्शन में शामिल हुए, तो उन्हें ड्रग्स के झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। इस कथित टिप्पणी के सामने आने के बाद छात्र संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यदि वीडियो वास्तविक है, तो यह नागरिक अधिकारों और पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।दूसरी ओर, पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से बचते हुए कहा है कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार वीडियो की तकनीकी जांच, संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी तस्वीर स्पष्ट की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है या छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया है, तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई दोनों की जा सकती हैं।

लाल सागर में हूथी हमला, सऊदी तेल टैंकर बने निशाना

यमन के ईरान-समर्थित हूथी विद्रोहियों ने गुरुवार तड़के कहा कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला किया है। वहीं, अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए, क्योंकि दोनों पक्ष अहम शिपिंग रास्तों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र पहले से ही ईरान-अमेरिका तनाव, गाजा संघर्ष और समुद्री सुरक्षा संकट के कारण बेहद संवेदनशील बना हुआ है। इस हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग की चिंता को और बढ़ा दिया है।रिपोर्टों के अनुसार हमला लाल सागर के उस हिस्से में हुआ जो बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य के बेहद करीब माना जाता है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारों में शामिल है, क्योंकि एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में तेल, गैस और अन्य सामान इसी रास्ते से गुजरते हैं। यदि यहां सुरक्षा संकट गहराता है, तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है।हूथी विद्रोही लंबे समय से यमन में सक्रिय हैं और उन पर पहले भी तेल प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों और समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हाल के महीनों में लाल सागर क्षेत्र में कई हमलों और ड्रोन गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैन्य तैनाती की है। इसके बावजूद हमलों का सिलसिला पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा।ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल टैंकरों पर हमले का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता। जैसे ही समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ता है, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देती हैं और जहाजरानी कंपनियों की लागत में इजाफा हो जाता है। इसका असर अंततः वैश्विक तेल कीमतों और उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली ऊर्जा लागत पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया से होने वाली आपूर्ति देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है।अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। कई देशों ने लाल सागर और बाब-अल-मंदब मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है। फिलहाल स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यदि ऐसे हमले लगातार जारी रहते हैं तो पश्चिम एशिया में समुद्री संघर्ष का खतरा और बढ़ सकता है, जिसका प्रभाव वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसके हमलों का मकसद "ईरान की उस क्षमता को और कम करना था जिससे वह इलाके के पानी से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचा सकता है।" अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर फिर से कंट्रोल हासिल करना चाहता है और इंटरनेशनल शिपिंग को बहाल करना चाहता है। ईरान के हमलों के जवाब में, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर फिर से नाकेबंदी लागू कर दी और पूरे देश में अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया। मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया कि अमेरिकी सेना जल्द ही पहाड़ के नीचे गहराई में बन रही ईरान की एक न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकती है।

थाईलैंड में एक सुरक्षा चौकी पर सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की और पाइप बम फेंके

थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत नाराथीवाट में एक सुरक्षा चौकी पर सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की और पाइप बम फेंके। इस हमले में पांच सैनिकों की मौत हो गई। रॉयल आर्मी के इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस कमांड की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। आईएसओसी रीजन-4 फॉरवर्ड कमांड के जनसंपर्क केंद्र की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सशस्त्र बलों द्वारा यह हमला 22 जुलाई की शाम नाराथीवाट प्रांत के रा-ण्गाए जिले के तंजोंग मास उप-जिला नगर क्षेत्र स्थित बुकेह सामी सुरक्षा चौकी पर हुआ। उस समय 45वीं रेंजर फोर्सेज रेजिमेंट के जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। हमले में मारे गए जवानों की पहचान सार्जेंट मेजर फर्स्ट क्लास तीरायुत सोमाकेई, रेंजर वॉलंटियर विमोल डाबथोंग, रेंजर वॉलंटियर नत्तासित केवसेना, रेंजर वॉलंटियर सोलाहुदिंग पी और रेंजर वॉलंटियर जकारिया जे-ना के रूप में हुई है। आईएसओसी रीजन-4 फॉरवर्ड कमांड ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद जवानों ने दक्षिणी सीमावर्ती प्रांतों में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों की तलाश शुरू की। बाद में नाराथीवाट के सी साखोन जिले में एक वाहन बरामद हुआ, जिसके बारे में माना जा रहा है कि हमलावरों ने उसी का इस्तेमाल किया था। आईएसओसी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, हमलावरों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से वाहन को जला दिया था। अधिकारियों ने हमले वाली जगह और वाहन बरामद होने के स्थान पर फोरेंसिक जांच की। आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए साक्ष्य जुटाए।

देशभर में भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश के कई हिस्सों में मानसून अब अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के लिए अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, कर्नाटक और राजस्थान सहित कई राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण मानसून की गतिविधियां काफी सक्रिय बनी हुई हैं। यही वजह है कि पश्चिमी और मध्य भारत के साथ-साथ उत्तर और पूर्वी राज्यों में भी तेज बारिश का दौर जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।लगातार बारिश के कारण कई शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में रेल सेवाओं और स्थानीय परिवहन पर भी असर देखने को मिल रहा है। पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात बाधित होने की आशंका है।राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा बलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रह सकता है। इसका सकारात्मक प्रभाव खरीफ फसलों पर पड़ सकता है, लेकिन यदि बारिश का यही सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा तो कई क्षेत्रों में बाढ़, फसल नुकसान और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिन प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर नई चेतावनियां जारी कर रहा है।

भारत ने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए इस्लामाबाद पर सीमा पार आतंकवाद को राज्य नीति के एक उपकरण के रूप में बार-बार इस्तेमाल करने और जम्मू-कश्मीर पर "झूठा नैरेटिव" फैलाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली ने यह भी दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग "हमेशा से रहा है, है और रहेगा। ये टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथानेनी हरीश ने बुधवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राकृतिक संसाधन शासन: शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव" विषय पर उच्च स्तरीय खुली बहस के दौरान कीं। बहस के दौरान पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया देते हुए, राजदूत हरीश ने कहा कि भारत का इरादा द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने का नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद द्वारा कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करके एक भ्रामक कहानी गढ़ने के बाद भारत को जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा। भारतीय राजदूत ने कहा मंच पर अन्य मुद्दों को उठाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उसने आज की चर्चा का दुरुपयोग करके अपनी झूठी कहानी को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति संवैधानिक और कानूनी रूप से स्थापित है, और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के बार-बार किए जाने वाले दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है, है और रहेगा। यह संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता है जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करना चुनता है। भारतीय राजदूत ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित एकमात्र अनसुलझा मुद्दा उन क्षेत्रों से जुड़ा है जिन पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में एकमात्र लंबित मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारत की संप्रभु भूमि पर खुला आक्रमण और अवैध कब्जा है।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ता तनाव ईरान-अमेरिका टकराव से वैश्विक बाजारों में चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र बन गया है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर संकट गहराने लगा है। दोनों देशों की ओर से आ रहे कड़े बयानों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यदि इस समुद्री मार्ग पर किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव या बाधा उत्पन्न होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।हॉर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल के बड़े हिस्से का परिवहन इसी रास्ते से होता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का निर्यात भी इसी मार्ग पर निर्भर है। इसलिए इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। यदि यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है।हाल के घटनाक्रम में ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके तेल निर्यात को रोका गया, तो क्षेत्र का कोई भी देश सुरक्षित रूप से तेल का निर्यात नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर किसी प्रकार का हमला या व्यवधान पैदा किया गया, तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इन बयानों ने पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव को और बढ़ा दिया है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव और बढ़ता है, तो इसका प्रभाव केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, शिपिंग लागत में इजाफा, महंगाई और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है।संयुक्त राष्ट्र और

कई प्रमुख देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। हालांकि फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी हैं, क्योंकि यहां की हर गतिविधि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

संपादक की कलम से

देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं केवल नौकरी या प्रवेश का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों, परिवारों की उम्मीदों और राष्ट्र की प्रतिभा का आधार भी होती हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा में पेपर लीक, अनियमितता या पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो नुकसान केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम पर जनता का भरोसा भी कमजोर पड़ता है। NEET पेपर लीक विवाद ने एक बार फिर यही चिंता सामने ला दी है।संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा जिस तरह राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया, उससे साफ है कि मामला अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। सत्ता पक्ष परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है, जबकि विपक्ष जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार का उत्तर देना उसका दायित्व। लेकिन जब बहस की जगह केवल हंगामा ले लेता है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का होता है, जिनके भविष्य को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है।प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। यदि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा होगा और दोषियों को शीघ्र सजा मिलेगी, तो परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा। लेकिन केवल अदालतें बना देना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण—प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर वितरण, डिजिटल सुरक्षा, निगरानी और मूल्यांकन तक—को आधुनिक तकनीक और सख्त जवाबदेही के साथ जोड़ा जाए।जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उस पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई ने इस पूरे विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि युवा अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी आवाज को विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर होना आवश्यक है। लोकतंत्र में संवाद का स्थान टकराव से कहीं अधिक प्रभावी होता है।यह भी समझना होगा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। इसका अर्थ है कि समस्या व्यक्तियों से अधिक व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों की है। इसलिए समाधान भी व्यापक होना चाहिए। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करना, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाना, साइबर निगरानी मजबूत करना और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना अब समय की मांग है।

NEET विवाद पर संसद में घमासान

चर्चा की सहमति के बाद भी इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

23 जुलाई 2026 को संसद का मानसून सत्र पूरी तरह NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन की गूंज में डूबा रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में हुई कथित गड़बड़ियों, छात्रों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इससे साफ हो गया कि NEET विवाद अब केवल शिक्षा व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है।सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। उनका कहना था कि उद्देश्य केवल राजनीतिक बहस करना नहीं, बल्कि ऐसा स्थायी समाधान तैयार करना है जिससे भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हों। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारों पर काम चल रहा है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।दूसरी ओर विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। विपक्ष का कहना है कि जब तक इस मामले में नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक संसद में होने वाली चर्चा का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होगा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है और छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही।संसद परिसर में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जवाब में सत्तापक्ष के सांसदों ने भी अलग प्रदर्शन कर सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के विरोध प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भी यह मुद्दा संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है।इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा ने बहस को नया मोड़ दिया। सरकार ने इसे छात्रों के हित में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल होगा। हालांकि विपक्ष ने इस घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि केवल नई अदालतें बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना ही सबसे बड़ा समाधान है।जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी संसद में जोर-शोर से उठा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे थे और उनकी आवाज को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।पूरे घटनाक्रम ने सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ उसे लाखों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा दोबारा कायम करना है, तो दूसरी ओर संसद में लगातार आक्रामक होते विपक्ष का सामना भी करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार और विपक्ष के बीच किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बनती, तो यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा सुधार, परीक्षा सुरक्षा और जवाबदेही जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बने रहने की पूरी संभावना है।

कल्याण बनर्जी का निलंबन, संसद में भाषा और मर्यादा पर नई बहस

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित अशालीन और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई संसद में अनुशासन, मर्यादा और सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक भाषा की सीमाओं पर नई बहस लेकर आई है।रिपोर्टों के अनुसार, इस विवाद की पृष्ठभूमि में सदन के भीतर हुई तीखी नोकझोंक और महिला सदस्यों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी शामिल थी। निलंबन के बाद विपक्षी दलों ने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर निर्णय वापस लेने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि जिस कथित घटना पर कार्रवाई हुई, वह सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुई थी, इसलिए नियमों की व्याख्या गलत तरीके से की गई।तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी यह मुद्दा हल्का नहीं रहा। एक ओर पार्टी के कुछ नेताओं ने कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया, तो दूसरी ओर कुछ सांसदों ने निलंबन को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। कल्याण बनर्जी ने भी अपने खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विरोधी उन्हें सदन से पूरी तरह बाहर नहीं कर सकते। वहीं बागी टीएमसी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ महिला सांसदों पर अपशब्दों वाली भाषा का सिलसिला लंबे समय से चल रहा था।यह मामला सिर्फ एक सांसद के निलंबन का नहीं, बल्कि संसद की संस्कृति का प्रश्न भी बन गया है। आज जब सदन पहले से ही NEET विवाद, छात्र आंदोलन और विपक्षी प्रदर्शनों से जूझ रहा है, तब इस तरह की टिप्पणी और उसका नतीजा राजनीतिक गरिमा की बहस को और गंभीर बनाता है। कई सांसदों का मानना है कि सार्वजनिक मंचों पर भाषा का स्तर गिरना लोकतांत्रिक विमर्श को नुकसान पहुंचाता है।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कार्रवाई संसद से स्पष्ट संदेश देती है कि व्यक्तिगत आक्षेप, खासकर लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में, अब ज्यादा सहन नहीं किए जाएंगे। आने वाले दिनों में विपक्ष की प्रतिक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष का रुख इस मुद्दे की दिशा तय करेगा।

उद्धव-राज ठाकरे साथ आए
NEET और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुंबई में मार्च की तैयारी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। वर्षों से अलग-अलग राजनीतिक राह पर चल रहे शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे अब एक साझा मुद्दे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने 26 जुलाई को मुंबई में संयुक्त विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। यह मार्च कथित पुलिस कार्रवाई और NEET पेपर लीक विवाद के खिलाफ आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक जानकार इसे केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत मान रहे हैं।घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस मार्च का मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवाज को मजबूती देना और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाना है। दोनों नेताओं का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और यदि परीक्षा प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है, तो इसका असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। इसी वजह से वे इस मुद्दे को केवल छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक और जनहित का विषय मान रहे हैं।उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे में उनका एक मंच पर आना अपने आप में बड़ी राजनीतिक घटना माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम विपक्षी राजनीति को नई ऊर्जा दे सकता है और राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा सकता है। हालांकि दोनों दलों ने इसे किसी चुनावी गठबंधन से जोड़ने से इनकार किया है और इसे केवल छात्रों के समर्थन में उठाया गया कदम बताया है।राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस संयुक्त मार्च का असर केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। यदि बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक संगठन और विपक्षी दल इसमें शामिल होते हैं, तो यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। इससे शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा।आने वाले दिनों में सभी की नजर 26 जुलाई के इस मार्च पर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विरोध प्रदर्शन में कितनी जनभागीदारी होती है और क्या इससे सरकार परीक्षा सुधारों और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर कोई बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा का मुद्दा अब महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ चुका है और इसका प्रभाव आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी देखने को मिल सकता है।

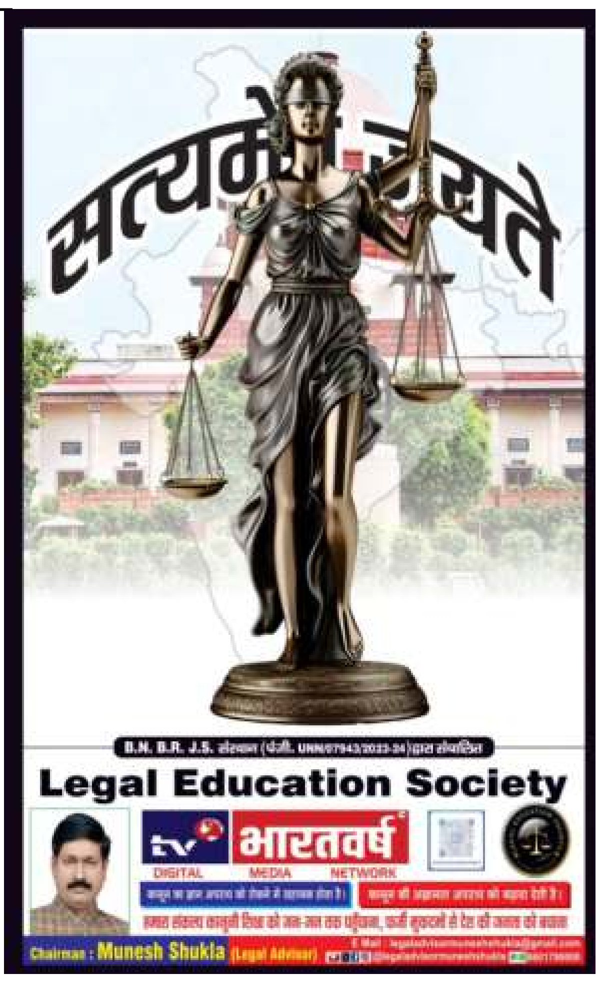

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूलिंग पर सवाल समावेशी शिक्षा की चुनौती फिर सामने

देश में शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की बात लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children With Special Needs - CWSN) की शिक्षा को लेकर सामने आई ताजा रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी इन लक्ष्यों से काफी दूर दिखाई देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का अर्थ केवल दिव्यांग बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है, जहां वे बिना किसी भेदभाव के सीख सकें और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें।रिपोर्ट के अनुसार देश के कई हिस्सों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अनेक सरकारी और निजी स्कूलों में व्हीलचेयर के अनुकूल रैंप, लिफ्ट, विशेष शौचालय और ब्रेल या सांकेतिक भाषा जैसी सुविधाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में

ऐसे शिक्षक भी नहीं हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण मिला हो। परिणामस्वरूप कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते, जबकि कुछ को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर बताई जा रही है, जहां परिवहन और सहायक संसाधनों की कमी बच्चों की शिक्षा में बड़ी बाधा बन रही है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समावेशी शिक्षा केवल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और स्थानीय प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बच्चों को समय पर चिकित्सकीय सहायता, सहायक उपकरण, मनोवैज्ञानिक सहयोग और प्रशिक्षित शिक्षकों का साथ मिले, तो उनकी सीखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। नई तकनीकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स और सहायक उपकरणों का प्रभावी उपयोग भी इन बच्चों की शिक्षा को अधिक आसान और सुलभ बना सकता है।विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि समाज में जागरूकता बढ़ाना उतना ही आवश्यक है जितना स्कूलों का बुनियादी ढांचा मजबूत करना। जब तक स्कूलों में ऐसा वातावरण तैयार नहीं होगा जहां हर बच्चा सम्मान और समानता के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके, तब तक समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। ऐसे में सरकार, स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिससे कोई भी बच्चा केवल अपनी विशेष आवश्यकता के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए।

एआई और ग्रीन स्किल्स पर नए प्रशिक्षण केंद्र, राज्यों में कौशल विकास को मिलेगी नई रफ्तार

देश में तेजी से बदलती तकनीक और रोजगार की जरूरतों को देखते हुए अब कौशल विकास कार्यक्रमों का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी दिशा में राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ग्रीन स्किल्स पर आधारित नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना, उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराना और भारत को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में रोजगार का बड़ा हिस्सा तकनीक और हरित ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में पैदा होगा, इसलिए यह पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन जैसी तकनीकों का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के कारण सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि युवाओं को केवल पारंपरिक प्रशिक्षण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नई तकनीकों में भी दक्ष बनाया जाए।इन प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रों और युवाओं को उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आधुनिक लैब, डिजिटल उपकरण, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और उद्योग विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा। कई राज्यों में स्थानीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप के बेहतर अवसर मिल सकें।

SA20 2027 के शेड्यूल का ऐलान 17 जनवरी से होगा आगाज

रोडरी को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन बॉल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के समापन के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस पुरस्कार को लेकर हो रही है, वह है स्पेन के स्टार मिडफील्डर रोडरी को मिला गोल्डन बॉल सम्मान। आमतौर पर यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को मिलता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करते हैं या सबसे अधिक असिस्ट देते हैं, लेकिन इस बार फुटबॉल ने एक अलग संदेश दिया। रोडरी ने पूरे टूर्नामेंट में न तो कोई गोल किया और न ही कोई असिस्ट दर्ज किया, इसके बावजूद उन्हें विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक फुटबॉल में केवल आंकड़े नहीं, बल्कि खेल पर नियंत्रण, रणनीतिक सोच और टीम को संतुलित रखने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।रोडरी पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की मिडफील्ड की रीढ़ बने रहे। उन्होंने हर मैच में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा, विपक्षी टीम के हमलों को रोका और टीम के आक्रमण की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके शांत स्वभाव, सटीक पासिंग और बेहतरीन पोजिशनिंग ने स्पेन को कई मुश्किल मुकाबलों में बढ़त दिलाई। मैदान पर उनका योगदान भले ही स्कोरशीट में नजर न आए, लेकिन खेल के जानकारों का मानना है कि स्पेन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका संतुलित प्रदर्शन था।फुटबॉल विशेषज्ञों का कहना है कि गोल और असिस्ट किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का केवल एक हिस्सा होते हैं। एक मिडफील्डर की असली जिम्मेदारी खेल की गति को नियंत्रित करना, रक्षा और आक्रमण के बीच संतुलन बनाना तथा पूरे मैच की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करना होती है। रोडरी ने पूरे विश्व कप में यही भूमिका बखूबी निभाई। इसी कारण तकनीकी समिति और विश्लेषकों ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी माना। विश्व कप 2026 का यह फैसला आने वाले वर्षों में फुटबॉल के मूल्यांकन के तरीके को भी नई दिशा दे सकता है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था तय, दर्शकों की निगाहें ऑनलाइन कवरेज पर

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आयोजन को लेकर तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं। इसी बीच खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रतियोगिता के सभी प्रमुख मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग, रीप्ले और हाइलाइट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रिपोर्टों के अनुसार दर्शक Sony LIV मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरे टूर्नामेंट की लाइव कवरेज देख सकेंगे। यह व्यवस्था उन करोड़ों खेल प्रशंसकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, जो अब पारंपरिक टेलीविजन के बजाय मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप जैसे डिजिटल माध्यमों पर खेल देखना पसंद करते हैं।पिछले कुछ वर्षों में खेल आयोजनों को देखने का तरीका तेजी से बदला है। पहले जहां अधिकांश दर्शक केवल टीवी प्रसारण पर निर्भर रहते थे, वहीं अब इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने डिजिटल स्ट्रीमिंग को नई पहचान दी है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के आयोजक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी प्रसारण रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि दर्शक किसी भी स्थान से अपने पसंदीदा मुकाबले लाइव देख सकेंगे। यदि कोई मैच छूट भी जाता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग और हाइलाइट्स बाद में आसानी से देखी जा सकेंगी। इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों, कोचों और खेल प्रेमियों को भी काफी सुविधा मिलेगी। युवा दर्शकों के बीच मोबाइल आधारित स्ट्रीमिंग की लोकप्रियता को देखते हुए यह फैसला समय के अनुरूप माना जा रहा है। भारत के लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, शूटिंग, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन जैसे खेलों में भारत से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। ऐसे में देशभर के करोड़ों दर्शक अपने खिलाड़ियों के मुकाबलों को डिजिटल माध्यम से आसानी से देख सकेंगे और हर पदक की दौड़ का हिस्सा बन पाएंगे।

चाइना ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का दम, आयुष शेट्टी की बड़ी जीत

भारतीय बैडमिंटन के लिए चाइना ओपन 2026 की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास कराया। सबसे बड़ी चर्चा युवा शटलर आयुष शेट्टी की रही, जिन्होंने विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर मौजूद अल्वी फरहान को हराकर टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर कर दिया। वहीं भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष एकल के प्रमुख दावेदार लक्ष्य सेन ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। इन परिणामों ने भारतीय बैडमिंटन अभियान को मजबूत शुरुआत दिलाई है और आगे के मुकाबलों के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं।आयुष शेट्टी की जीत को केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारतीय बैडमिंटन की नई पीढ़ी के उभरते आत्मविश्वास का प्रतीक भी माना जा रहा है। विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन आयुष ने धैर्य, आक्रामक खेल और बेहतरीन रणनीति के दम पर यह जीत हासिल की। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मुकाबले किसी खिलाड़ी के करियर में निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करते हैं।दूसरी ओर, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए जीत दर्ज की। सिंधु लंबे समय से भारतीय बैडमिंटन की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रही हैं और उनसे इस टूर्नामेंट में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं लक्ष्य सेन ने भी शानदार लय दिखाते हुए अगले दौर में जगह बनाई। उनकी जीत ने पुरुष एकल वर्ग में भारत की उम्मीदों को और मजबूत किया है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बैडमिंटन अब केवल कुछ अनुभवी खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में कई युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे भारत की खिलाड़ी तैयार करने की प्रणाली और प्रशिक्षण व्यवस्था की सफलता भी दिखाई देती है। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में मिली ये सफलताएं खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ आगे के कठिन मुकाबलों के लिए भी सकारात्मक माहौल तैयार करेंगी।

'हां, मैं बर्गर खाऊंगा' वायरल वीडियो पर जवाब चर्चा में

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया कथित तौर पर एक मॉल स्थित बर्गर किंग के आउटलेट में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि जब पार्टी के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब क्या पार्टी का एक प्रमुख चेहरा मॉल में बर्गर खा रहा था? हालांकि, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने का समय और परिस्थितियां स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सकी हैं.

NEET पर बयान बना मजाक

NEET पेपर लीक को NEET अखबार लीक बोलने के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन को ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर काफी लोग उनके इस वीडियो को शेयर कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

इन दिनों NEET पेपर लीक मामले को लेकर विरोध- प्रदर्शन का दौर व्यापक रूप लेता जा रहा है. कल आंदोलनकारियों के संसद मार्च के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी बात रखी. इसी बीच NEET पेपर लीक को NEET अखबार लीक बोलकर सांसद रवि किशन सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. ऐसे में जानते हैं क्या है पूरा मामला. NEET पेपर लीक के विरोध में जंतर- मंतर पर CJP काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है. इसको लेकर सोनम वांगचुंग भूख हड़ताल पर हैं. इसी कड़ी में कल सीजेपी और दूसरे आंदोलनकारियों ने सांसद मार्च भी निकाला था. इसमें जमकर बवाल हुआ. इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग सरकार को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. इसी बीच बीजेपी सांसद रविकिशन ने संसद के सत्र के बाद मीडिया को बयान देने के दौरान एक ऐसी गलती कर गए कि अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को नीट अखबार लीक मामला कह दिया. दरअसल, कल हुए विरोध प्रदर्शन और नीट पेपर लीक मामेल पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज देश के युवाओं और विद्यार्थियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. संसद का सत्र खत्म होने के बाद जब सांसद बाहर निकलने लगे तो बीजेपी सांसद रवि किशन से प्रतिक्रिया ली जा रही थी. उनसे सवाल किया गया कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा? इस पर रवि किशन ने प्रधानमंत्री की बात दोहराई और उन्होंने कहा कि 13 जो लोग पकड़े गए हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील रखा जाए. जो भी सबसे बड़ा वकील हो, उसे रखा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की जुर्रत न करे या NEET अखबार को लीक करने की ताकत रखे.

अनोखा प्यार, ऑटो में पत्नी की तस्वीरें, रोज ताजे फूल

सच्चा प्यार कैसा होता है? शेरो-शायरी में इसका जिक्र मिलता है, फिल्मों में इसकी कहानियां दिखाई जाती हैं. लेकिन सच्चे प्यार की परिभाषा शायद प्यार करने वाले भी शब्दों में नहीं बता पाते. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो देखकर लोग यही कह रहे हैं कि अगर सच्चा प्यार होता है, तो शायद ऐसा ही होता है.

बेंगलुरु के एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. उनके ऑटो की स्टीयरिंग के सामने बेले के फूलों की माला टंगी रहती है. पत्नी के निधन को आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी हर सुबह उनके लिए ताजे फूल खरीदते हैं और ऑटो

चलाने से पहले उनकी तस्वीर पर चढ़ाते हैं. इस भावुक कहानी को इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर आशीष मैथ्यू ने शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके के एक ट्रैफिक सिग्नल से होती है, जहां उन्होंने एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को अपने ऑटो के अंदर बड़े प्यार से फूल सजाते हुए देखा.

मौत से रोमांचक मुकाबला

बारिश के मौसम में पहाड़ी सड़कों पर सफर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक बाइकर कुछ सेकंड के लिए मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया. उसकी बाइक फिसलन भरी सड़क पर बेकाबू होकर सीधे गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है. लेकिन आखिरी सेकंड में जो हुआ, उसने हर किसी की सांसें रोक दीं. इंस्टाग्राम पर अरसू नाम के यूजर ने यह वीडियो 'सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ' कैप्शन के साथ शेयर किया है. वीडियो में अरसू अपने

हेलमेट कैमरे से बारिश के बीच पहाड़ी सड़क का नजारा रिकॉर्ड कर रहे हैं. उनसे कुछ दूरी आगे उनके साथी बप्पी बर्मन बाइक चला रहे होते हैं. शुरुआत में सबकुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन एक मोड़ पर अचानक पूरी कहानी बदल जाती है. कैसा था नजारा बारिश की वजह से सड़क बेहद फिसलन भरी थी. जैसे ही बप्पी बर्मन मोड़ पर पहुंचे, उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से सड़क पर फिसलते हुए खाई की तरफ बढ़ने लगी. कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब बाइक सीधे खाई में गिर जाएगी.

स्टारडम बनाम कहानी: क्या केवल विजय का करिश्मा काफी है?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसे विजय के अभिनय करियर की अंतिम फिल्म बताया जा रहा है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद यह उनकी विदाई फिल्म मानी जा रही है, इसलिए दर्शकों की भावनात्मक अपेक्षाएं भी इससे जुड़ी हुई थीं। रिलीज के पहले दिन सिनेमाघरों के बाहर उमड़ा प्रशंसकों का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि विजय का स्टारडम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है। लेकिन शुरुआती प्रतिक्रियाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी फिल्म की सफलता केवल स्टार की लोकप्रियता से तय हो सकती है, या फिर मजबूत कहानी और प्रभावी प्रस्तुति भी उतनी ही जरूरी है?फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक ओर विजय के प्रशंसक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एंट्री सीक्वेंस और अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे उनके करियर की यादगार विदाई बताया है। वहीं दूसरी ओर कुछ दर्शकों ने फिल्म की कहानी, गानों और संवादों को कमजोर बताते हुए "क्रिंज" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह विभाजित प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि आज का दर्शक केवल बड़े सितारे के नाम पर फिल्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा का दर्शक काफी बदल चुका है। अब वह सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और वैश्विक कंटेंट के संपर्क में है। ऐसे में उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। यदि कहानी कमजोर हो या पटकथा में नवीनता न हो, तो बड़े से बड़ा सितारा भी आलोचना से नहीं बच पाता। दूसरी ओर, अच्छी कहानी वाली अपेक्षाकृत छोटे बजट की फिल्में भी दर्शकों का भरपूर समर्थन हासिल कर लेती हैं। यही बदलाव भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।'जन नायकन' की चर्चा में एक और दिलचस्प पहलू बॉबी देओल की भूमिका रही। शुरुआती प्रतिक्रियाओं में उनके नकारात्मक किरदार की काफी सराहना की गई है। यह दर्शाता है कि आज दर्शक केवल नायक ही नहीं, बल्कि प्रभावशाली सहायक पात्रों और मजबूत खलनायकों को भी उतना ही महत्व देते हैं। किसी भी फिल्म की सफलता अब पूरे कलाकार समूह और संतुलित कहानी पर अधिक निर्भर करती है।हालांकि शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत कर सकती है। यदि पहले दिन और शुरुआती सप्ताहांत में अनुमानित कमाई होती है, तो यह विजय के स्टारडम की ताकत का प्रमाण होगी। लेकिन किसी भी फिल्म की वास्तविक सफलता केवल शुरुआती कमाई से नहीं, बल्कि लंबे समय तक दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ से तय होती है।'जन नायकन' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि थलपति विजय के अभिनय सफर का अंतिम अध्याय भी मानी जा रही है। स्वाभाविक है कि उनके प्रशंसकों के लिए यह भावनात्मक अवसर हो। लेकिन फिल्म उद्योग के लिए इससे बड़ा संदेश यह है कि बदलते दौर में स्टारडम और अच्छी कहानी—दोनों का संतुलन ही स्थायी सफलता की कुंजी है। दर्शक अब केवल तालियों से नहीं, बल्कि अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया से भी फिल्मों का भविष्य तय कर रहे हैं। यही भारतीय सिनेमा के परिपक्व होते दर्शक वर्ग की सबसे बड़ी पहचान है।

NEET विवाद पर अखिलेश यादव का हमला बोले- पेपर लीक नहीं, सुनियोजित तरीके से कराए जा रहे हैं

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए और छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई।

दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्व में हजारों छात्र पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा बिल्कुल साफ है। सरकार को छात्रों और युवाओं की चिंताओं और मांगों को मान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा बहुत स्पष्ट है। सरकार को छात्रों और युवाओं की चिंताओं को समझना चाहिए। खुद संबंधित मंत्री ने माना कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पेपर लीक हो गया था, इसलिए नीट परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। इससे हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। पेपर लीक अब नई बात नहीं रह गई है। यह बार-बार हो रहा है। लगता है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। केंद्र के समय में करीब 150 लीक हुए तो यूपी में भी 20 हो चुके हैं। 'डबल इंजन' सरकार कहलाने वाली यह सरकार बार-बार ऐसा होने दे रही है, यह हैरान करने वाली बात है। अखिलेश ने कहा कि पेपर सिर्फ लीक नहीं हो रहे, बल्कि इन्हें लीक करवाया जा रहा है। इसका मकसद नौकरियां अपनी मनमानी से भरना है। आरक्षण का मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है। जब तक संबंधित मंत्री इस्तीफा नहीं देते, हम संसद में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों की मांगों को पूरा किया जाए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की कार्रवाई को हिटलर की तानाशाही से जोड़ते हुए कहा कि छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के 24 जुलाई को प्रस्तावित जनसभा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। इस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार बड़ी अनोखी है। अनुमति आखिरी समय पर देती है। देखिएगा, जब सिर्फ एक दिन बचेगा तब शंकराचार्य को अनुमति दे दी जाएगी। तब वे तैयारी कैसे करेंगे, लोगों को कैसे जुटाएंगे? जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि उन्हें मुश्किल में डाला जा सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश और धार्मिक नेताओं की सभाओं में रोड़े अटकाने से साफ है कि सरकार असहज हो गई है। नीट घोटाले और पेपर लीक की घटनाएं पिछले कई महीनों से सुर्खियों में हैं। छात्रों का कहना है कि मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि कुछ लोग पैसे और सिफारिश से आगे निकल जा रहे हैं। अखिलेश यादव की इस आक्रामक रुख से साफ है कि विपक्ष अब संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाए रखना चाहता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति कार्यालय का किया घेराव

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने गुरुवार दोपहर कुलपति कार्यालय का घेराव किया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी के एसी और इंटरनेट सही कराने व टाइमिंग बढ़ाने की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो दोबारा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि इसके बाद होने वाले आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि साइबर लाइब्रेरी में पढ़ाई का माहौल लगातार प्रभावित हो रहा है। कई एसी लंबे समय से खराब हैं। इंटरनेट सेवा भी नियमित रूप से बाधित रहती है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने मांग की कि सभी खराब एसी तत्काल ठीक कराए जाएं। इंटरनेट सेवा सुचारु की जाए और लाइब्रेरी का समय प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जाए। छात्र नेता अनुराग चौधरी ने कहा कि पिछले महीने कुलपति के साथ हुई वार्ता में विश्वविद्यालय प्रशासन ने साइबर लाइब्रेरी को सप्ताह के सातों दिन खोलने और उसके संचालन समय में विस्तार करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है।

विभूतिखंड इलाके में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया

लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। अमेरिका के नागरिकों को फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बनकर ठगा जा रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर के चार संचालकों को गिरफ्तार किया है। मौके पर मिले 35 कॉलिंग एजेंटों की भूमिका की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 जुलाई की रात विभूतिखंड थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह जलवा बार के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से साइबर हाइट बिल्डिंग की चौथी मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 420A में फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली। इसके बाद क्राइम टीम के साथ रात करीब 2:55 बजे छापा मारकर कॉल सेंटर पकड़ा। पुलिस ने मौके से प्रतापगढ़ निवासी सूरज त्रिपाठी, उसके रिश्तेदार विवेक पांडेय और राहुल त्रिपाठी व मुंबई निवासी तकनीकी विशेषज्ञ आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि सूरज पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जबकि आकाश फर्जी वेबसाइट और VOIP सिस्टम संचालित करता था। जांच में पता चला कि गिरोह गूगल पर विज्ञापन के जरिए फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट को प्रमोट करता था। वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर अमेरिका से कॉल आने पर VOIP के जरिए कॉल लखनऊ स्थित कॉल सेंटर पहुंचती थी। यहां एजेंट खुद को कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताते थे। इसके बाद कॉल क्लोजर खुद को FTC या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जैसे सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते या लालच देकर गिफ्ट कार्ड, सोना या नकदी के रूप में रकम ऐंठ लेते थे। पुलिस के अनुसार अमेरिका में मौजूद गिरोह के सदस्य ठगी की रकम इकट्ठा करते थे। इसके बाद हवाला के जरिए पैसा लखनऊ भेजा जाता था। कर्मचारियों को भी नकद भुगतान किया जाता था, ताकि लेन-देन का कोई डिजिटल रिकॉर्ड न रहे।

शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में गुरुवार को निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा

लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में गुरुवार को निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सातवीं मंजिल पर प्लास्टर का काम कर रहे चार मजदूर पाइप टूटने से नीचे गिर गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही महानगर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं। घायलों को तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तहसीलदार सदर जय प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह कार्य के दौरान पाइप का टूटना सामने आया है। अब तक चार मजदूरों (छोटू कुमार (28), सुरेंद्र कुमार (45), निक्कू (24), मोनू (25)) के घायल होने की पुष्टि हुई है। सभी घायल मजदूर समस्तीपुर, बिहार के रहने वाले हैं। वहीं मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल (एमडीआरवी) की रेस्क्यू टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एफएसओ हजरतगंज रामकुमार रावत ने बताया कि सातवीं मंजिल पर प्लास्टर का काम चल रहा था। इसी दौरान ही इसी दौरान हादसा हुआ। चारों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल किसी मजदूर की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घायल मजदूरों का इलाज नीरा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। प्रशासन हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है।

गोमती नदी के ऊपर सफेद झाग की मोटी परत

बारिश शुरू होते ही गोमती नदी में प्रदूषण बढ़ गया है। शहर के कई हिस्सों में नदी के ऊपर सफेद झाग की मोटी परत दिखाई देने लगी है। नालों का बिना शोधित पानी तेजी से गोमती नदी में पहुंच रहा है। जिससे नदी का पानी और ज्यादा प्रदूषित हो गया है। लखनऊ के 27 बड़े नाले सीधे गोमती नदी में गिर रहे हैं। इन नालों के जरिए सड़ी गलियां पत्तियां, पौधे, मिट्‌टी और दूसरी गंदगी लगातार नदी में पहुंच रही है। बारिश के दौरान नालों में पानी का बहाव भी बढ़ गया है। तेजी से पानी नदी में गिरता है। इससे पानी में हवा मिल जाती है और झाग बन रहा है। इससे साफ है कि नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका दुष्प्रभाव नदी में रहने वाली मछलियों और दूसरे जलीय जीवों पर भी पड़ रहा है। शहर में सीवर के पानी को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए गए हैं। बारिश के समय इनमें जरूरत से ज्यादा पानी पहुंचने लगता है। ऐसे में कई बार पूरा पानी तरह से साफ नहीं हो पाता है। कुछ हिस्सा सीधे नदी में चला जाता है। इसका असर गोमती की पानी की गुणवत्ता पर साफ दिखाई दे रहा है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 81 दिन की गविष्ठि (गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध) यात्रा के दौरान उनके और उनके समर्थकों को कई जगह परेशान किया गया। लखनऊ में प्रस्तावित गौ गर्जन अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम को प्रशासनिक परिस्थितियों के चलते अब डिजिटल माध्यम (वर्चुअल) से आयोजित करने का फैसला लिया गया है। शंकराचार्य ने दावा किया कि यात्रा के दौरान कई स्थानों पर उन्हें रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी गई। हमें रात में सड़क पर समय बिताना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 जुलाई के कार्यक्रम में आने वाले कई कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही रोक दिया गया है। कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा रही है और कई जगह बिजली तक काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब अभी भी हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, जबकि हमें कार्यक्रम की अनुमति मिली हुई है। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि यहां रावण राज आ चुका है। उन्होंने कहा कि पहले 24 जुलाई को आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन में दोपहर 12 बजे गौ गर्जन अक्षौहिणी संकल्प का सार्वजनिक आयोजन होना था, लेकिन अब इसे प्रत्यक्ष की बजाय डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच गौ माता की रक्षा को लेकर संकल्प और आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है। यात्रा का उद्देश्य गौमाता की रक्षा के लिए जनजागरण करना था। यात्रा के दौरान प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद किया गया। यात्रा के दौरान उन्हें प्रदेशभर में लोगों का समर्थन मिला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर परिसर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने की बात कही थी, लेकिन वह इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी बाद में सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी। शंकराचार्य ने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान दिए जाने चाहिए।

जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ सदर तहसील के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया

उन्नाव में गंगा के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने गुरुवार दोपहर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के साथ सदर तहसील के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें परियर गंगा घाट स्थित बाबू बंगला और माना बंगला शामिल थे। इस दौरान उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर निरीक्षण कर सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश दिए है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परियर गंगा घाट पहुंच मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने संबंधित ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने चार दिन के भीतर अधिक संख्या में श्रमिक लगाकर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ के दौरान ग्रामीणों के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पहले से सुरक्षित शरणालयों का चयन कर लिया जाए। इससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव से जुड़ी सभी तैयारियां पहले से पूरी रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी टीमें पूरी तरह सक्रिय रहें और उनके पास पर्याप्त मात्रा में एंटी-वेनम के साथ-साथ डायरिया, बुखार, खांसी-जुकाम तथा अन्य आवश्यक दवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने बाढ़ के समय स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी न आने देने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए भूसा और चारे की समुचित व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राहत सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन समय रहते उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। इस दौरान जयप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार गोंड, क्षेत्राधिकारी सफीपुर दीपक यादव, उपजिलाधिकारी सदर राजेश कुमार विश्वकर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बाढ़ से निपटने की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

लेखपाल और ग्राम प्रधान पर जमीन आवंटन में मिलीभगत का आरोप

उन्नाव के सफीपुर तहसील क्षेत्र के गुरुधरी ग्राम सभा में क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम प्रधान पर जमीन आवंटन में मिलीभगत का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों को मनचाहे चक आवंटित किए जा रहे हैं, जबकि गरीब किसानों को दूर-दराज की बंजर भूमि दी जा रही है। इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि गांव चकबंदी में होने के कारण गरीब किसान परेशान हैं। अनुसूचित जाति के कई परिवार लगभग 60 वर्षों से आबादी के नजदीक की जमीन पर काबिज हैं, लेकिन उन्हें अब खराब और ऊबड़-खाबड़ उसर बंजर जमीन आवंटित की जा रही है। पार्टी ने यह भी बताया कि जो जमीन पहले आवासीय क्षेत्र के नजदीक कूड़ा घर के लिए थी, उसे अब काफी दूर कर दिया गया है। वहां न तो कोई रास्ता है और न ही सुरक्षा का इंतजाम। यह क्षेत्र जंगल से घिरा है, जहां नशेड़ी और जुआरी सक्रिय रहते हैं, जिससे महिलाओं के साथ किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। आरोप है कि ग्राम सभा में लगभग 150 बीघा बंजर और बचत की भूमि है, जिस पर प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आजाद समाज पार्टी ने मांग की है कि इन अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए और गरीब किसानों को न्याय दिलाया जाए।

सीएमएस डॉ. अरविंद कुमार आनंद ने गुरुवार सुबह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया

जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अरविंद कुमार आनंद ने गुरुवार सुबह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, ओपीडी और पैथोलॉजी सहित विभिन्न विभागों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की और मरीजों को बेहतर उपचार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएमएस डॉ. अरविंद कुमार आनंद ने बताया कि वह समय-समय पर अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वे स्वयं भी ओपीडी में पहुंचकर मरीजों की समस्याएं सुनते हैं। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से यह जांच की गई कि कहीं चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर की दवा तो नहीं लिखी जा रही है। इसके अलावा, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का मरीजों के प्रति व्यवहार कैसा है, इसकी भी लगातार निगरानी की जाती है। सीएमएस ने स्पष्ट किया कि मरीजों के साथ सम्मानजनक और व्यवहार कुशल तरीके से पेश आना अस्पताल की प्राथमिकता है। सीएमएस ने अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके तीमारदारों के बैठने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीज खड़े मिले, जिसके बाद संबंधित कर्मचारियों को उन्हें तत्काल बैठाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों ने तुरंत व्यवस्था कर मरीजों को बैठाया। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह निरीक्षण के समय तक महिला अस्पताल की ओपीडी में 232 पर्चे बनाए जा चुके थे, जबकि लगभग 180 टोकन जारी किए गए थे। मरीजों का उपचार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा था और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं मिली। डॉ. आनंद ने पैथोलॉजी विभाग का भी निरीक्षण किया, जहां सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। अस्पताल में दवा वितरण, जांच और मरीजों के उपचार की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई छोटी-मोटी समस्या सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाता है।

उन्नाव में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

उन्नाव में गुरुवार दोपहर को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शहर के जीआईसी ग्राउंड में इकट्ठे हुए छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं और "इंकलाब जिंदाबाद", "भारत माता की जय", तथा "शिक्षा बचाओ" जैसे नारे लगाए। उनका आरोप था कि शिक्षा व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर छात्रों की आवाज को लगातार अनसुना किया जा रहा है और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शन में शामिल छात्र राजन ने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। एक अन्य छात्र कुश सिंह ने बताया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देशभर में छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं और उन्नाव के छात्र भी इसी कड़ी में शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने सरकार से शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की। उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा बना रहे। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

उन्नाव में बुधवार शाम एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया

उन्नाव में बुधवार शाम एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के भूपतिपुर गांव की रहने वाली नीतू (40) पत्नी स्व. रमेश ने सुसाइड कर लिया। 10 साल पहले उनके पति रमेश का निधन हो गया था। पति की मौत के बाद नीतू अपनी दो बेटियों के साथ ससुराल में ही रह रही थीं। उनका मायका असोहा थाना क्षेत्र के गंगाखेड़ा गांव में है। गुरुवार दोपहर जिला पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतका के पिता लोकनाथ ने बताया कि उनकी बेटी ने ससुराल स्थित घर में फांसी लगाई। उन्होंने बताया कि नीतू अपने पीछे दो बेटियों को छोड़कर चली गई। हालांकि, आत्महत्या के पीछे के कारणों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लोकनाथ ने बताया कि परिवार को अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि नीतू ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जब उनसे किसी पर शक या किसी प्रकार की कार्रवाई की इच्छा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। प्रभारी निरीक्षक भुवन सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पोनी रोड चौड़ीकरण परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान गुरुवार को भी जारी रहा

उन्नाव शहर में पोनी रोड चौड़ीकरण परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। इस कड़ी में कई मकान मालिकों ने अपने मकानों और दुकानों के आगे बने चबूतरे, छज्जे और अन्य निर्माण स्वयं हटा दिए हैं। हालांकि, झंडा चौराहा के आगे के कुछ निवासियों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने अभी तक उनके भवनों पर स्पष्ट नापजोख और निशान नहीं लगाए हैं। पीडब्ल्यूडी ने बीते शनिवार को पोनी रोड चौड़ीकरण योजना के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया था। इस दौरान लोहिया स्कूल से लेकर बिंदा नगर तक सड़क किनारे बने चबूतरे, रैंप और अन्य अवैध निर्माण हटाए गए थे। विभाग ने भवन स्वामियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया था, ताकि भारी मशीनों के उपयोग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मोहलत मिलने के बाद बिंदा नगर से लेकर पोनी रोड झंडा चौराहा तक बड़ी संख्या में लोगों ने अपने निर्माण स्वयं हटाने शुरू कर दिए। गुरुवार को भी कई मकानों और दुकानों के सामने मजदूर दीवारें, छज्जे और चबूतरे तोड़ते देखे गए। निर्माण हटाने के दौरान सुरक्षा कारणों से सड़क के कुछ हिस्सों को बांस-बल्लियों से घेर दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ा। दूसरी ओर, झंडा चौराहा के आगे के भवन स्वामियों और दुकानदारों ने विभाग पर स्पष्ट माप और निशान न लगाने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि बिना सही माप के निर्माण तोड़ने से आवश्यकता से अधिक हिस्सा टूट सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने विभाग से पहले स्पष्ट सीमांकन कराने की मांग की है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर नवीन चंद्र मिश्रा ने बताया कि बिंदा नगर से लेकर पोनी रोड तिराहा तक आवश्यक निशान लगाए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें। यदि निर्धारित समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग जेसीबी मशीन से कार्रवाई करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्रवाई के दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामी की होगी।

योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला

बोले- छात्रों के आंदोलन की आड़ में अशांति फैलाने की कोशिश

यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे, को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। कांग्रेस NEET-UG पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है।

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में जारी राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद सत्र के दौरान जिस प्रकार विरोध-प्रदर्शन किए गए, उसका उद्देश्य केवल सरकार का विरोध करना नहीं था, बल्कि देश में अशांति का माहौल बनाना और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देना भी था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विपक्ष ने संसद से लेकर सड़कों तक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की, जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो।योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान हंगामा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार, विपक्ष ने छात्रों की भावनाओं को भड़काकर आंदोलन को व्यापक राजनीतिक अभियान में बदलने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इससे छात्रों की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा कम और राजनीतिक टकराव अधिक देखने को मिला। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन को राजनीतिक स्वार्थ का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मूल मुद्दा कमजोर पड़ जाता है।मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय कश्मीरी पंडितों को आतंकवाद के कारण घाटी छोड़नी पड़ी, तब विपक्ष ने प्रभावी ढंग से उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दों पर काम कर रही है, तब वही राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता जैसे विषयों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि अशांति फैलाने की कोशिश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली, तो किसानों को भड़काने की कोशिश की गई और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सरकार के खिलाफ वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया। हालांकि विपक्ष इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि वह केवल छात्रों की आवाज संसद और जनता के बीच उठाने का काम कर रहा है। NEET विवाद अब पूरी तरह राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने तर्कों के साथ जनता के सामने हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अब भी लाखों छात्र हैं, जो निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और अपने भविष्य की सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी के साथ-साथ परीक्षा सुधारों पर ठोस कदम उठाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्तार अंसारी के गैंग पर बड़ी कार्रवाई, हथियार लाइसेंसों की पूरी छानबीन शुरू कर दी गई

बाहुबली मुख्तार अंरी के गैंग पर यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिवंगत मुख्तार के गैंग के सदस्यों और उनके करीबियों को दिए गए हथियार लाइसेंसों की पूरी छानबीन शुरू कर दी गई है। अब तक 51 लाइसेंसों पर खरीदे गए 145 हथियारों का भौतिक सत्यापन चल रहा है। इस जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके चलते अफजाल अंसारी समेत तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वाराणसी जोन के डीआईजी के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी। इस टीम ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश तक जाकर डीएम कार्यालयों और हथियार दुकानों के रिकॉर्ड चेक किए। जांच के दौरान कई लाइसेंस और हथियार खरीद-बिक्री के कागजात गायब मिले। कुछ हथियारों का पता ही नहीं चल पा रहा है कि वे अब कहां हैं और किसके पास हैं। पुलिस का आरोप है कि पुराने हथियार लिपिकों ने मिलीभगत करके मूल कागजात गायब करवा दिए। इससे हथियारों की ट्रैकिंग और सही इस्तेमाल की जांच में दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा मामला अफजाल अंसारी का है। उनके नाम पर जारी लाइसेंस नंबर 1188 P-2 की फाइल और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड गायब पाए गए। इस लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल नंबर 830405 की लोकेशन भी साफ नहीं है। इस पूरे मामले में गाजीपुर कोतवाली थाने में मुकदमा नंबर 535/2026 दर्ज किया गया है।इस केस में अफजाल अंसारी के अलावा तत्कालीन पहले हथियार लिपिक असफाक अहमद और दूसरे लिपिक गौरी शंकर राम पर भी केस दर्ज हुआ है। इन पर आईपीसी की धारा 409, 120-बी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल रहा है।

अब मंदिर की पूजा-पाठ, अनुष्ठान और सारी धार्मिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संतों को सौंप दी गई

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की धार्मिक गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब मंदिर की पूजा-पाठ, अनुष्ठान और सारी धार्मिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संतों को सौंप दी गई है। ट्रस्ट की बैठक में नई धार्मिक समिति बनाई गई है, जिसमें अयोध्या के प्रमुख संत शामिल हैं। इस समिति का फैसला धार्मिक मामलों में अंतिम माना जाएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि इस नई धार्मिक समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में महंत दिनेंद्र दास (निर्मोही अखाड़ा), महंत कमलनयन दास (मणिराम दास छावनी), महंत डॉ. रामानंद दास (रामकथा कुंज), राजकुमार दास (रामवल्लभा कुंज), महंत मिथिलेशनंदिनी शरण जैसे स्थानीय संतों को जगह दी गई है। इसके अलावा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और जगद्गुरु स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ भी सदस्य होंगे। नौ सदस्यीय इस समिति में अयोध्या के संतों की संख्या ज्यादा है। ट्रस्ट का मकसद है कि राम मंदिर में सब कुछ वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुसार चले। पूजा-अर्चना से लेकर बड़े-बड़े पर्वों तक की निगरानी अब यही समिति करेगी। समिति को पांच बड़े अधिकार दिए गए हैं। इनमें मंदिर की रोजाना पूजा और अनुष्ठानों की निगरानी, रामनवमी, विवाह पंचमी, सीता नवमी जैसे त्योहारों की तारीख तय करना और उनका आयोजन, विशेष यज्ञ-हवन और वैदिक कार्यक्रमों की योजना बनाना शामिल है। इसके अलावा पुजारियों के प्रशिक्षण, उनकी नियुक्ति, उनके आचरण और ड्रेस कोड पर नजर रखना तथा अयोध्या के मठ-मंदिरों, संत समाज और गुरुकुलों से लगातार संपर्क बनाए रखना भी समिति की जिम्मेदारी होगी। बैठक में महासचिव और खाली ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब इन पदों पर नाम तय करने के लिए दो सितंबर को फिर बैठक बुलाई गई है।

खेत में चारा लेने गई थी मां, बेटे ने वहीं रची खौफनाक साजिश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां वन विभाग से मिलने वाले पांच लाख रुपये के मुआवजे के लालच में एक बेटे ने अपनी ही मां की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पूरे गांव और पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा नाटक रचा कि हर किसी को लगा महिला की मौत गुलदार के हमले में हुई है। आरोपी ने खुद को भी मां को बचाने की कोशिश करने वाला बेटा बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी पूरी कहानी को झूठ साबित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र निवासी बीरो देवी सोमवार को अपने बेटे बहाल सिंह के साथ खेत में चारा लेने गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान बहाल सिंह ने सुनसान खेत में अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि खेत में गुलदार ने उसकी मां पर हमला कर दिया और वह उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो सका। आरोपी की चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इलाके में पहले से गुलदार की दहशत होने के कारण लोगों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। देखते ही देखते गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि क्षेत्र में लगातार गुलदार दिखाई देने के बावजूद वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम रहा है, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।